

द बगि पकिचर: ईरान के साथ दोस्ती दाँव पर

परचिर्चा के प्रमुख बदि

- भारत-ईरान की दोस्ती पर संकट
- ईरान की प्रमुख चिंता
- क्या है ईरान द्वारा प्रदत्त भारत के वशिषाधिकार
- अमेरिकी तानाशाही कहाँ तक जायज़
- भारत के लिये आगे की राह

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

भारत और ईरान के संबंध प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। सदियों से भारतीय और ईरानी समाज कला, स्थापत्य, वचिार और परंपराओं, संस्कृति एवं वाणजिय के माध्यम से आपस में जुड़े रहे हैं। गुजरात में 2001 में भीषण भूकंप आया था तो ईरान सहायता करने वाले प्रमुख देशों में से एक था। इसी प्रकार भारत ने भी ईरान की वपिदा के समय उसकी मदद की। कति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ही दो देशों के बीच संबंध बनते या बगिड़ते हैं।

- हाल ही में ईरान ने सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के वसितार में नविश करने के अपने वादे को पूरा नहीं करने के लिये भारत की आलोचना की और कहा कि यदि भारत ईरान से आयातित तेल में कटौती करके इसकी पूर्त सिऊदी अरब, रूस, इराक, अमेरिका और अन्य देशों से करता है तो ईरान भारत को उपलब्ध कराए गए वशिषाधिकारों को समाप्त कर देगा।
- ध्यातव्य है कि अमेरिका ने ईरान से होने वाले तेल के आयात को लेकर भारत, चीन समेत कई देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाले सभी देशों के लिये चार नवंबर तक की समय-सीमा नरिधारित की है और इस तारीख तक सभी देशों को अमेरिकी प्रतबिंध झेल रहे ईरान के साथ तेल आयात को पूरी तरह बंद करना होगा।

क्यों लगाए हैं अमेरिका ने ईरान पर प्रतबिंध?

- वयिना में आयोजित बैठक के दौरान ईरान और P5+1 देशों (अमेरिका, ब्रिटिन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी) के मध्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम समझौते (JCPOA) पर जुलाई 2015 में सहमत हुई।
- मई 2018 में अमेरिका ने इज़राइल द्वारा उपलब्ध कराए गए खुफिया दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहा है, साथ ही वह सीरिया, यमन और इराक में शिया लड़ाकों और हजिबुल्लाह जैसे संगठनों को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है।
- इसी वज़ह से अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया और ईरान पर फरि से आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतबिंध लगा दिये। अमेरिका द्वारा ईरान पर इन प्रतबिंधों को लगाने का मुख्य उद्देश्य ईरान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना है।
- अमेरिका ने इस समझौते को तोड़ने के पीछे दूसरी वज़ह इसका बेहद उदार होना बताया है। अमेरिका के मुताबकि यह समझौता ईरान को तय सीमा से कहीं अधिक हैवी वॉटर (परमाणु रिएक्टरों के संचालन में इसका इस्तेमाल होता है) प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जाँचकर्त्ताओं को जाँच के मामले में सीमति अधिकार देता है।
- ईरान समझौते के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, इस बात की जाँच की ज़मिमेदारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को दी गई थी। IAEA को हर तीन महीने में एक रपिर्ट दर्ज करनी होती है। अब तक कसि भी रपिर्ट में ईरान पर शक की बात नहीं की गई है।

‘संयुक्त व्यापक क्रयिान्वयन योजना’ (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) या ‘वयिना समझौता’

- ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिये वर्ष 2015 में ईरान तथा P5+1 देशों (अमेरिका, चीन, ब्रिटिन, फ्राँस, रूस और जर्मनी) के मध्य एक समझौता कयिा गया।
- समझौते के अनुसार ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की नयिमति जाँच के लिये राजी हुआ ताकि सुनिश्चित कयिा जा सके कि वहाँ परमाणु हथियार बनाने पर

काम नहीं चल रहा है।

- समझौते में ईरान द्वारा पराधिकृत यूरेनियम भंडार को 96 प्रतिशत तक घटाना और अपने सभी संयंत्रों को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिये खोलना शामिल है।
- इस समझौते के तहत ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्द्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी।
- इस समझौते का मकसद था परमाणु कार्यक्रमों को रोकना। इन शर्तों के बदले में पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे।

(टीम दृष्टि इनपुट)

अमेरिकी प्रतिबंधों का ईरान पर प्रभाव

- ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान से तेल का आयात करने वाले देशों को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिये वे देश अपने तेल आयात में कटौती कर सकते हैं जिसका सीधा असर ईरानी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
- अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण पटरी पर लौटती ईरान की अर्थव्यवस्था को फरि से गहरा धक्का लगा है। ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा उत्पादित सामानों (दवाइयों और मशीनों इत्यादी) की ईरान में भारी कमी हो गई है।
- अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान का बैंकिंग सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन कदमों का मकसद ईरान के वित्तीय संस्थानों को वैश्विक पूंजी बाजार से दूर करना है। ये वही पूंजी बाजार है जिनमें ईरान को परमाणु समझौते के बाद कुछ जगह मिली थी।
- जून 2018 के अंत तक अधिकतर यूरोपीय बैंकों ने ईरान के साथ अपने वित्तीय लेन-देन बंद कर दिये। नतीजतन, यूरोपीय कंपनियों को भी ईरान के साथ आयात-निर्यात के अपने सौदों का हिसाब करने में मुश्किलें आ रही हैं।

भारत को लेकर ईरान की चिंता

- चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान से तेल आयात में कटौती नहीं करने का नरिणय लिया है, जबकि भारत ने अभी इस संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ईरान भारत से भी उसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है।
- भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण में सहयोग किया है, साथ ही चाबहार से लेकर जाहेदान तक रेल पथ के निर्माण के लिये 500 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि के निवेश का वादा किया है। ईरान इस बात से चिंतित है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत अपने निवेश में कमी कर सकता है।
- कुछ रपॉर्टर यह दर्शाते हैं कि भारत सरकार ने 4 नवंबर की अमेरिकी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकारी तेल कंपनियों को वैकल्पिक स्रोतों की एक रूपरेखा तैयार करने के लिये कहा है।
- अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से जून महीने में भारत के ईरान से तेल आयात में 15.9 फीसदी की कमी आई है। जून महीने में भारत ने ईरान से प्रतिदिन 5,92,800 बैरल तेल का आयात किया, जबकि मई महीने में यह 7,05,200 बैरल प्रतिदिन था।
- ईरान ने आरोप लगाया है कि चाबहार बंदरगाह के वसितार के लिये भारत अपने वादे के मुताबिक निवेश करने में असफल रहा है। भारत से उम्मीद की जाती है कि वह इस संबंध में जरूरी कदम उठाएगा क्योंकि चाबहार बंदरगाह में उसका सहयोग और भागीदारी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- ईरान इस बात से भी चिंतित है कि इससे पहले भी भारत ने कई मौकों पर अमेरिका के दबाव में अपनी रणनीति बदली है, जैसे- वर्ष 2005 और 2009 में भारत ने अमेरिका के दबाव में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव में ईरान के वरिद्ध मतदान किया था।

क्या है ईरान द्वारा प्रदत्त भारत के विशेषाधिकार

- ईरान अन्य देशों के लिये 30 दिन की तुलना में भारत को 60 दिन की क्रेडिट सीमा देता है।
- साथ ही ईरान ने भारत को सीधे रुपए में भुगतान करने की भी सुविधा प्रदान की थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुल राशि का 55% भुगतान यूरोपीय बैंकों में किया जाएगा तथा शेष 45% राशि का भुगतान भारत स्थित बैंक में किया जाएगा जिसका उपयोग भारत से आयात के लिये किया जाएगा।
- बाद में यूरोपीय बैंकों द्वारा भुगतान बंद किये जाने की स्थिति में ईरान ने भारत को 100% भुगतान रुपए में करने की सुविधा दी, यह व्यवस्था ईरान के साथ P5+1 देशों की संधि होने तक जारी रही।
- इसके बाद पुनः 55% भुगतान यूरो और 45% रुपए में करने की व्यवस्था की गई।
- इसके अतिरिक्त ईरान द्वारा भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिये माल ढुलाई में भी छूट प्रदान की जाती है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

भारत का रुख

- भारत ने इस संबंध में कहा है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही मानेगा, इसके इतर भारत और किसी राष्ट्र द्वारा लगाए गए

प्रतर्बिधों को मानने के लिये बाध्य नहीं है और पूरव में भी भारत ने ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र के ही प्रतर्बिधों को मान्यता दी थी ।

- वर्ष 2010 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लाए गए मानवाधिकार के मसले पर मर्यामार, उत्तर कोरिया और ईरान के पक्ष में अमेरिकी प्रस्ताव के वरिद्ध मतदान किया था ।
- हाल ही में भारत ने येरुसलम को इज़राइल की राजधानी बनाने के अमेरिकी प्रस्ताव के वरिद्ध में मतदान किया था तथा उत्तर कोरिया में उच्चायोग बंद करने के अमेरिकी फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था । अतः अमेरिका के दबाव में आने की बात पूरी तरह सत्य नहीं है ।
- सरकार ने कहा है कि भारतीय बास्केट में कई देशों का करूड शामिल है । भारत को दुनिया में कसी देश से तेल खरीदने में आपत्त नहीं है । लेकिन जहाँ तक ईरान से तेल खरीदने का सवाल है तो भारत इस बारे में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाएगा ।

भारत से ईरान को लाभ

- मई 2016 में अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रपिकषीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ईरान में विकास कार्यों में तेज़ी देखी गई और 1.5 वर्ष में ही शहीद बहेसती पोर्ट का परचालन शुरू कर दिया गया जिससे इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता सालाना 8.5 मिलियन टन यानी पछिले वर्ष के 2.5 मिलियन टन की तुलना में तीन गुना अधिक बढ़ गई ।
- ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक राष्ट्र है । भारत के कुल तेल आयात में ईरान का हस्सिा तकरीबन 10.4 प्रतशित है । वतित वर्ष 2017-18 के पहले 10 महीनों में यानी अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के बीच भारत ने ईरान से 184 लाख टन कच्चा तेल खरीदा ।
- ईरान वर्तमान में ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है जो कि 2.7 मिलियन बैरल प्रतदिनि कच्चे तेल का नरियात करता है । भारत चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल नरियातक देश है ।
- ईरान पर यूरोपीय देशों के प्रतर्बिध हटने के बाद ईरान के साथ भारत के तेल व्यापर में लगातार वृद्धि देखी गई है । प्रतर्बिध हटाने से पूरव ईरान भारत का आठवाँ बड़ा तेल आयातक था लेकिन प्रतर्बिधों के हटने के पश्चात् ईरान अब तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है ।

क्या यह अमेरिका की मनमानी है?

- पछिले कई वर्षों से अमेरिका ने ईरान पर इसलिये आर्थिक प्रतर्बिध लगाए थे ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे और जब 2016 में ईरान ने JCPOA पर सहमति जताई तो इसका हर तरफ स्वागत किया गया ।
- कति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका की यह रणनीति रही है कि ईरान का वरिद्ध किया जाए, इसलिये उसने JCPOA को एक उदार समझौता कहा और इससे बहार निकल गया, अमेरिका न सरिफ भारत पर बल्कि उन सभी देशों पर दबाव बना रहा है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं ।
- पछिले कुछ समय में अमेरिका ने कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से खुद को अलग किया है जैसे- पेरसि जलवायु समझौता और UNESCO इत्यादी ।
- अमेरिका ने कई वर्षों से उत्तर कोरिया पर कई प्रतर्बिध लगाए थे लेकिन हाल ही में कमि जोंग तथा डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका ने भवषिय में प्रतर्बिधों में कई तरह की ढील देने की बात कही है ।
- अतः इन सब घटनाओं ने वरिध में अमेरिका की साख खराब की है, साथ ही अमेरिका के एकाधिकारवादी रवेये को दर्शाया है ।

आगे की राह

- भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी स्वतंत्र वरिध नीति का पालन करता है । भारत अगले 10-20 वर्षों में वरिध का सबसे बड़ा उर्जा संसाधन बाज़ार होगा, अतः कई आपूर्तिकर्ताओं के लिये भारत से अपने संबंधों में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक होगा ।
- भारत का ईरान में बड़ा नरिध है, साथ ही चाबहार बंदरगाह भी सामरिक रूप से भारत के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है जो कि मध्य एशिया तक भारत की पहुँच सुनरिचित करता है । अतः भारत को ईरान के साथ मलिकर एक बेहतर समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रति करना होगा ।
- भारत ने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है जिससे यह तय किया जा सके कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतर्बिध कतिने उचित हैं क्योंकि ईरान ने न तो कोई सैन्य कार्यवाही की है और न ही ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने के कसी दावे की पुष्टि IAEA द्वारा की गई है ।
- ईरान के साथ तेल व्यापार को नवंबर तक शून्य किया जाना पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है इससे भारत के चालू खाता घाटे में वृद्धि होने की संभावना है साथ ही, तेल की कीमतों में वृद्धि से भी इनकार नहीं किया जा सकता ।

नरिधकर्ष: हालाँकि अपने बयान के कुछ समय बाद ही वरिध ईरानी राजनयिक ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया । ईरान और भारत के संबंध अत्यंत पुराने हैं, अतः अस्थिर तेल बाज़ार में भारत की स्थिति को समझा जा सकता है । यद्यपि भारत आधिकारिक तौर पर यह मानता है कि नरिध प्रतर्बिध व्यवस्था का पालन करने की बाध्यता नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है फरि भी इन सब वरिधों के मध्य भुगतान का मुद्दा सर्वाधिक वरिधरणीय होगा । यह देखते हुए कि ईरान भारत के कुल तेल आयात का लगभग 10 प्रतशित हस्सिा %E